ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4 बैलगाड़ी से मिट्टी ढोकर ग्रामीणों से बना डाला सुदामडीह का गंगा मैदान

रविवारीय, 16 - 22 फरवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-28, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

पानी खरीदेंगे, पर बचायेंगे नहीं

मुख्य संवाददाता

रांची : अब शीत ऋतु अपने समापन पर है। पिछले मॉनसून में अच्छी बारिश से जलसंकट से रांची के जलाशयों में जल एकत्र हुआ था। और इन चार महिनों में लोगों को पानी की कमी से दो चार नहीं होना पड़ा था। अब गर्मियां शुरू होंगी और राजधानी के कई इलाकों में जलस्तर शुरूआत में ही नीचे चला जायेगा। कई कुयें होली के समय ही जवाब दे जाते हैं और सरकारी जलापूर्ति के बाधित होते ही यहां जलसंकट गहरा जाता है। पानी खरीदने से लेकर सरकार को कोसने और टैंकरों के पास मारपीट आम बात हो जाती है। लेकिन क्या आम लोगों ने सरकार ने खुद अपनी जिम्मेदारी निभाई है?

रांची और आस पास का क्षेत्र जल संकट से तकरीबन हर साल ग्रस्त होता है। इसके बावजूद हम जल संरक्षण को लेकर बहुत लापरवाह रहे हैं? अब तक जितने भी प्रयास जल संरक्षण के हुये हैं उनमें से ज्यादतर खानापुर्ति साबित हुये हैं। इक्का दुक्का एकल प्रयासों में ही इसकी सफलता दिखी है। उदाहरण के लिये हम रांची हाइकोर्ट में बने वाटर हार्वेस्टिंग को एक सफल तकनीक मान सकते हैं, लेकिन लोगों में इसके प्रति कोई खास जागरूकता नहीं है। रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिये वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपने घरों में बनवाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसे रांचीवासियों ने एक बोझ समझ लिया और कुछ ने इसकी खानापुर्ति कर ली। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तव में अगर इसे रांचीवासी अपनाते हैं तो यहां जलसंकट कभी नहीं होगा।

देश के अन्य जलसंकट से ग्रस्त इलाकों में जहां लोग पानी की अहमियत समझते हैं वहीं झारखंड का दुर्भाग्य है कि हम जलसंकट तो झेलते हैं लेकिन जलसंरक्षण करने में तत्पर नहीं रहते। अपने जलाशयों ,नदियों ताल तलैयों को हम झारखंडी जिस बेरहमी से बर्बाद करते जा रहे हैं इसकी बानगी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी ?

अतिक्रमण रोकने में सरकारें विफल

नदियों और रांची के जलाशयों को बचाने के नाम पर शोर बहुत होते रहा है, पर यह एक हकीकत है कि जब इन जलाशयों का अतिक्रमण होता है तो सरकारें इन्हें रोकने के प्रति लापरवाह रही हैं। गोंदा जलाशय ही लें तो समय समय पर यहां से अतिक्रमण हटाये गये, आवासों को तोड़ा तक गया लेकिन फिर से कुछ महिनों में वापस और मजबूत मकान बना लिये गये। एक पूर्व विधायक तो ये सब होने देते थे ताकि उस इलाके में संरक्षण देकर वोट बैंक बढा सकें। रांची में कई छोटी बरसाती नदियों को लुप्त करके घनी रिहायशी कॉलोनियां बन गयी हैं और अब उन नदियों तालाबों को कोई नामोनिशान नहीं रह गया है। बारिश के मौसम में ये इलाके जलजमाव झेलती हैं।

नदियों, झीलों को बर्बाद करने में सरकार और जनता बराबर की सहयोगी

रांची में विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर बारी-बारी से तालाबों और नदियों को बर्बाद किया गया है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकार्ड देखें तो हम पायेंगे कि तकरीबन जितने भी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया उसमें से कुछ लुप्त ही हो गये और कुछ का प्राकृतिक जलश्रोत ही खत्म कर दिया गया। चुटिया का तालाब , मधुकम तालाब, बरियातू का जोड़ा तालाब, करम टोली तालाब , जेल तालाब इन सभी का सौंदर्यीकरण कुछ इस तरह से हुआ है कि करोड़ो रूपये फूंक कर ठेकेदारों से लेकर अन्य के वारे न्यारे तो हो गये लेकिन तालाब खुद मरते गये। डिस्टिलरी तालाब तो खत्म ही हो गया। इन कामों में किसी पर्यावरणविद् की राय लेने के बजाय साहबों ने सिर्फ मोटा बजट बनाया और छोटे छोटे तालाबों के सौंदर्यीकरण में करोड़ो रूपये खर्च कर डाले। भले आज चार पांच करोड़ की लागत से करमटोली तालाब देखने में सुंदर लगता हो, पर अगर पर्यावरर्णीय दृष्टी से देखें तो इस तालाब को नुकसान पहुंचाया गया है।

जुडको के हाथों संवरने की बाट जोह रही हरमु नदी बुरी हालत में है। करोड़ों फूंकने के बाद भी नदी जस की तस नाले की तरह ही है। इसके उद्गम को दुरूस्त करने और तल को साफ करने पर कोई काम नहीं किया गया, लेकिन गंदे काले जलयुक्त इस नदी के किनारों को जरूर पत्थर से पाट दिया गया है। वहीं आम लोगों ने भी जलाशयों के ग्रीनलैंड और कैचमेंट में आवास बना लिये हैं।

रविवार को हवाइअड्डे पर उपराष्ट्रपति का राज्यपाल ने किया स्वागत

चरित्र, समर्पण, आचरण और क्षमता का एक लीडर में होना जरूरी है: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू

रांची : उपराष्ट्रपति एम. वैंकेया नायडू ने भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप, पॉलिसी एंड गवर्नेंस के तहत नेतृत्व क्षमता और सुशासन विषय पर आईआईएम के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक लीडर में, नेतृत्व करने वाले में चरित्र, समर्पण, आचरण और क्षमता का होना बेहद जरूरी है। तभी नेतृत्व करने वाला अपनी जिम्मेदारियों के साथ सकारात्मक परिणाम समाज और देश को दे सकता है। लीडर का यह मतलब नहीं कि वह राजनीति से ही जुड़ा है। लीडर किसी भी क्षेत्र का में हो सकता है। एक लीडर में जाति, समुदाय, नकदी और आपराधिकता नहीं होना चाहिए। वे इन सब चीजों को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये बातें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कही। वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा। आईआईएम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। सुशासन बेहतर सरकार की पहचान है। सुशसान से निर्णय लेने की क्षमता, भ्रष्टाचार का खात्मा होता है। विकास दिखाई देता है। नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके। राष्ट्रपिता ने भी राम राज की कल्पना की थी। जहां सिर्फ सुशसान हो।

कोल इंडिया के सीएमडी गोपाल सिंह को मिला ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड

रांची :कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह को एनर्जी एंड इनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला। नई दिल्ली में द एनर्जी एंड इनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा 15 से 17 फरवरी तक आयोजित 10वीं वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट में उन्हें यह अवार्ड मिला। यह पुरस्कार उनके नेतृत्व में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम उर्जा एवं कोयला मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से प्रतिवर्ष द एनर्जी एंड इनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा दिया गया। पेज 3 भी देखें

मिलिबग से आम के फसल की सुरक्षा की जानकारी दी

नौणी विवि के विशेषज्ञों ने बागवानों को आम के पेड़ों की देखरेख करने की सलाह दी है। हर वर्ष आम में मिलीबग कीट की समस्या रहती है। इसके नियंत्रण को बागवान आम के पेड़ों पर एल्काथीन 15 से 20 सेमी चौड़ी पट्टी मुख्य तने पर जमीन से करीब आधा मीटर ऊपर तक लपेटें, ताकि कीट के शिशु जमीन से निकलकर पेड़ों पर न चढ़ पाएं। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोनिंग का यदि कुछ कार्य रह गया है तो उसे जल्द पूरा कर लें। पेड़ों के घाव पर ब्लॉकटॉक्स या चैबाटिया पेस्ट जरूर करें। मटर फसल को जीवाणु से बचाने के लिए उसमें बाड़ लगाने का कार्य भी शुरू कर दें। स्ट्रैप्टोसाइक्लीन 10 ग्राम को 100 लीटर पानी में मिलाकर उस्-ाका छिड़काव करे। यह जानकारी नौणी विवि के विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश भारद्वाज ने दी।

पंजाब की अपेक्षा झारखंड में मात्र एक फीसदी किसान ही करते हैं ट्रैक्टर का उपयोग

राजेश कंमार

रांचीः झारखंड में पंजाब की अपेक्षा मात्र एक प्रतिशत किसान ट्रैक्टर का उपयोग करते है। उक्त बातें रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 14 फरवरी को आयोजित एक दिवसीय तकनीकी एवं मशीनरी प्रत्यक्षण मेला में उभकर सामने आई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के निर्देश पर कृषि अभियंत्रण विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में 6 अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनओं की तकनीकी एवं मशीनरी का प्रत्यक्षण और प्रदर्शन किया गया। मेले का उदघाटन मुख्य अतिथि बीएयू निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ आरएस कुरील ने किया। मौके पर डॉ कुरील ने प्रदेश में उत्पादन एवं उत्पादकता की बढ़ोतरी के लिए कृषि योग्य भूमि का समुचित उपयोग एवं रकबा बढ़ाने की बात कही। उन्होंने प्रदेश में 20-25 लाख टन खाद्यान की कमी को पूरा के लिए इन बातों पर बेहतर कार्ययोजना और रणनीति बनाने पर जोर दिया। प्रदेश की उबड़ और पथरीली एवं छोटे - छोटे खेत में सामूहिक खेती, एक साथ बड़े पैमाने पर खेती और सहकारिता आधारित खेती पर जोर दिया। इस कार्य में फार्म मशीनरी को बेहद सुगम साधन बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के कृषि आय में बढ़ोतरी में उन्नत तकनीकी एवं फार्म मशीनरी बेहद उपयोगी साबित हो रही है।

विशिष्ठ अतिथि भूमि संरक्षण निदेशक फणीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने समय से खेती, समय की बचत, श्रम आदि लागत में कमी एवं फसल नुकसान के बचाव में फार्म मशीनरी मददगार एवं लाभकारी कहा। उन्होंने प्रदेश के सभी 265 प्रखंडो में संचालित कृषि उपकरण बैंक की सहायता से किसानों को सस्ती दर पर फार्म मशीनरी का उपयोग करने को कहा। निदेशक शोध डॉ डीएन सिंह ने प्लास्टिक कल्चर तकनीक से बेमौसमी सब्जी खेती तथा फसल कटाई उपरांत तकनीक से फसल उत्पाद के प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन से किसानों को अधिक कृषि लाभ लेने को कहा। डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने कहा कि पंजाब के 70 प्रतिशत के अपेक्षा झारखंड में मात्र एक प्रतिशत किसान ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। .....शेष पेज 3 पर

19 फरवरी को सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में हृदय रोग का निःशुल्क चिकित्सीय शिविर

रांची : सी.सी.एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह की पहल पर कायाकल्प मॉडल के अंतर्गत स्वास्थय कार्यक्रम सुपर स्पेशियलिटी क्लीनिक केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर मे आगामी19फरवरी, 2020 को हृदय रोग की जांच एवं चिकित्सीय सलाह दी जायेगी।हैदराबाद के प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. पी.के. कुचलाकान्ति (कार्डियोलॉजिस्ट)19 फरवरी, को प्रातः 09 बजे से केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर, कांके रोड़, रांची आयेंगे, जहॉ वे मरीजों की जॉच करेंगे तथा चिकित्सीय सलाह देंगे। इस निःशुल्क चिकित्सीय सलाह का सभी झारखंड-वासी लाभ उठा सकते हैं। मरीज के पास यदि पुराने ईलाज की रिर्पोट/ जॉच के पेपर हों तो उसे अवश्य अपने साथ लाये।

अब उपलब्ध होगा हरी मिर्च का पाउडर

रांची : अब तक हम तीखेपन के लिये सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर ही उपयोग करते आये हैं। लेकिन अब हरे मिर्च का पाउडर भी बाजार में उपलब्ध होगा। देश के एकमात्र भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीच्यूट आफ वेजटेबल रिसर्च(आइआइवीआर) ने सभी वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुये हरी मिर्च का पाउडर तैयार किया है। इसका पेटेंट भी हो चुका है।संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुधीर सिंह की टीम ने इस पर 2010 में ही शोध शुरू किया था। 2013 में प्रारंभिक सफलता मिलने पर इसके व्यावसायिक उत्पादन की पूर्ण स्वीकृति के लिये अब चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भेजा गया है। डॉ. सुधीर सिंह बताते हैं कि पहली बार हरी मिर्च से पाउडर बनाने की विधि का लाइसेंस आइआइवीआर के पास है। इस पाउडर में सबसे अधिक तीखापन और हरा रंग मौजूद है। जब किसी कंपनी को लायसेंस दिया जायेगा तो उसे पैकेट पर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंस फ्राम आइआइवीआर , वाराणसी अंकित रहेगा। वहीं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के निदेशक डॉ. जगदीश सिंह का कहना है कि कई वर्षों के परिश्रम के बाद हमें इसमें सफलता मिली है अब इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा इससे किसानों की आया में भी वृद्धी होगी।

स्कैन एंड पे तकनीक से लेन देन होगा बहुत आसान

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी छोटे व्यापारियों को बेहतरीन सौगात

रांची : देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय स्टेट बैंक मध्यम और छोटे स्तर के व्यापारियों के व्यापार को सुगम बनाने के लिए बड़ें स्तर पर काम कर रहा है। वर्तमान डिजीटल युग में पेमेंट को लेकर बैंक ने एक नये प्रणाली की शुभारंभ किया है। यह प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित और सुगम है। इस प्रणाली में एक डिवाइस (उपकरण) के माध्यम से लेन देन को तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है। झारखंड स्थित जोनल कार्यालय सहित लगभग सभी भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं पर यह डिवाईस उपलब्ध है। आधार कार्ड के माध्यम से उपयोग किया जाने वाला यह उपकरण उपयोग में बॉयोमेट्रिक पेमेंट का सबसे बेहतर माध्यम हो गया है जिसे भारतीय स्टेट बैंक के करेंट एकाउंट से जोड़कर सहजता से संचालित किया जा सकता है। सिर्फ अंगुलियों के निशान के माध्यम से भी इस उपकरण का उपयोग कर सौ प्रतिशत त्वरित लेन-देन संभव है। इस लेने देन का संदेश लेन-देन के साथ ही मोबाइल पर उपलब्ध हो जाता है। क्यू आर कोड से जुड़ा यह लेन-देन निः शुल्क है और इसे आइटी की भाषा में स्केन एंड पे कहा जाता है। बैंकिंग की भाषा में इसे रियल टाइम मनी ट्रांसफर कहा जाता है जिसमें तुरंत एकांउट से पैसा ट्रांसफर होता है। अभी इसकी सीमा दो हजार रुपये है जो निकट भविष्य में पांच हजार रुपये बढ़ाया जा सकता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर छोटे और कम लेन देन के लिए सब्जी बिक्रेजा, परचून दुकान वाले,छोटे व्यापारी इसक उपकरण का उपयोग करके अपना सुरक्षित लेन-देन कर सकते हैं। अधार से जुड़े होने के कारण यह भीम, पेटीएम, यानो से भी इसे जोड़ा जा सकता है। इस तकनीक से लेन-देन का हर दिन का ब्यौरा ई मेल पर भी उपलब्ध होता है ।

एसबीआइ इस दिशा में ठोस कार्य कर रहा है और इसकी जानकारी किसी भी इच्छुक को वेबसाइट पर या किसी भी ब्रांच पर उपलब्ध है। किसी प्रकार की फ्राड से यह उपकरण सुरक्षित है क्योंकि इसका क्यू आर कोड और आधार से जुड़ा होने से पूरी प्रकिया पारदर्शी और बेहतरीन है।

जंगल कटाई से आ रही हैं जानलेवा बीमारियां

अनु जैन रोहतगी

चीन के वूहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। 2003 में चीन से ही सार्स बीमारी की शुरुआत हुई थी, जिसने लगभग आठ हजार लोगों को अपना शिकार बनाया और 800 से ज्यादा लोगों की जान ली। वहां से आगे बढ़ते हुए कोरोना वायरस ने उससे कहीं कम समय में 1100 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 40 हजार से ज्यादा लोगों को मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया है। इसका खतरा अब वर्ल्ड इकॉनमी पर भी मंडरा रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के चलते दुनिया की जीडीपी 0.2 से 0.3 फीसदी तक नीचे आ सकती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के आधे से अधिक देश अमेरिका से ज्यादा व्यापार चीन से करते हैं। कोरोना के पीछे पहली वजह मांसाहार की बताई जा रही है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में फैलने वाले अधिकतर जानलेवा इन्फेक्शन जूनोटिक हैं। जूनोटिक मतलब जानवरों से इंसान में फैलने वाले इनफेक्शन। कोरोना से पहले एचआईवी, जीका, बर्ड फ्लू, इबोला, निपाह, सार्स, मर्स आदि भी जूनोटिक नेचर के ही थे। एक्सपर्ट कई बार चेता चुके हैं कि जंगलों की कटाई मनुष्य में जूनोटिक बीमारियां फैलने की बड़ी वजह हो सकती है। मानव जहां भी जंगल काटकर अपने घर और खेत बना रहा है, जंगली जानवर भी अपना घर खोजते हुए वहीं पहुंच रहे हैं। इंसान और जानवरों के बीच कम होती यह दूरी जानवरों में न जाने कब से पल रहे खतरनाक वायरसों को खुला मैदान दे रही है।जानवरों से निकली बीमारियों में सार्स का

जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। 2012 में मध्य-पूर्व के देशों में ऊंटों से फैली बीमारी मर्स से मरने वालों की संख्या 850 के आसपास थी। मध्य-पश्चिमी अफ्रीका में लंबे समय तक सक्रिय इबोला ने अफ्रीका के तीन देशों में 11,310 लोगों की जान ली, जबकि वेस्ट नाइल फीवर से अकेले अमेरिका में अब तक दो हजार लोग मर चुके हैं। निपाह वायरस ने सबसे पहले मलयेशिया में तबाही मचाई तो जीका वायरस ने ब्राजील में काफी बच्चों की जान ली या उन्हें स्थायी रूप से मंदबुद्धि बना दिया।

वैज्ञानिक खोज से पता चला कि 1997 में इंडोनेशिया के जंगलों को आग लगाई गई तो वहां के चमगादड़ निपाह का वायरस लेकर मलयेशिया पहुंच गए। वहां निपाह ने सुअरों में घर बनाया जिसके बाद वहीं पर वर्ष 1999 में सुअर पालने वाले 265 लोग निपाह के शिकार हुए और लगभग 105 लोगों की जान गई। हाल में निपाह वायरस का प्रकोप केरल तक में देखा गया। वर्ष 2003 और 2015 के बीच की गई एक स्टडी से पता चला कि इस बीच 10 फीसदी जंगल खत्म होने से मलयेशिया के मामले हर साल 3 फीसदी बढ़े हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों में फैले नमी वाले इलाके मच्छरों की पसंदीदा जगह होते हैं। जंगलों के कटने से मच्छरों के झुंड इंसानी बस्तियों को अपना शिकार बना रहे हैं। एनवायरमेंट रिसर्च लैटर्स में चेताया गया है कि जंगलों की कटाई से मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है जो किसी भी वायरस के तेजी से पनपने में मददगार हो रहा है। कुछ देशों में जानवरों के बाजार को भी नए वायरसों का ठिकाना बताया जा रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन बाजारों में मौजूद जानवरों में पनपने वाले तमाम नए वायरस जो इनके मुंह से निकलने वाली लार, पंख, खाल और कच्चे मीट में मौजूद होते हैं, हवा, पानी, मच्छर और दूसरे जरियों से इंसान तक पहुंच रहे हैं। खासकर चीन में वेट एनिमल मार्केट बड़ी संख्या में हैं, जहां सांप, लोमड़ी, कुत्ते, मगरमच्छ, चमगादड़, बिच्छू और तमाम जंगली व समुद्री जीव जिंदा बेचे जाते हैं।

पहले सार्स और अब कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के उन्हीं इलाकों में उभरा, जो इन बाजारों के बहुत पास पड़ते थे। समय आ गया है कि हम पर्यावरण सुरक्षा पर अपने घरेलू मामलों जितना ही ध्यान दें और जंगली जानवरों तथा इंसानों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। एक्सपर्ट कई देशों में चल रही वेट एनिमल मार्केट पर पूरी तरह से बैन की मांग भी कर रहे हैं। उनकी मांग पर गंभीरता से सुनवाई होनी चाहिए, वरना वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब हमारी सारी ताकत नए-नए वायरसों से अपनी जान बचाने और उनसे निपटने के उपाय खोजने में ही जाएगी।

(ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने है)

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi

93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

खाद्य पदार्थों में मिलावट

कुछ साल पहले भारत से निर्यात किये जाने वाले मिर्च पाउडर पर ब्रिटेन ने रोक लगा दी थी। उसके इस रोक के बाद सारे यूरोपीय देशों ने भी भारत से मिर्च पाउडर का आयात बंद कर दिया था। ब्रिटेन का कहना था उसने लैब जांच में पाया है कि भारत से आयातित इस मिर्च पाउडर में कैंसरकारक तत्व हैं जो भारतीय किसानों के खेती करने के दरम्यान खतरनाक उर्वरकों के डाले जाने के कारण है। भारत सरकार के लाख दलीलों के बाद भी ब्रिटेन ने रोक लगा दी। यह एक उदाहरण है कि यूरोप अपने खाद्य सामग्रियों की शुद्धता को लेकर कितना सजग है। ठिक इसके उलट हमारे देश में मिलावट एक व्यावसाय है। पहले गावों में लोग कहते थे कि अनाज के व्यावसायी महीन कंकड़ पत्थर चुन कर रखते थे जिन्हें वो अनाजों में मिलाया करते थे और इसका भी एक रेशियो तय था कि एक क्विंटल चावल में कितना महीन कंकड़ मिलाना है। और आश्चर्य की यह सब भारतीय समाज में शुरू से ही स्वीकार्य रहा है। हम यह मान कर चलते रहे हैं कि बाजार से खरीदे गये अनाज में कंकड़ पत्थर रहेंगे ही। लेकिन आज की मिलावट ज्यादा खतरनाक स्तर की है। कंकड़ पत्थर तो चुन कर निकाला जा सकता था लेकिन अब ज्यादतर खाद्य पदार्थ तैयार रूप में ही खरीदने की संस्कृति है। अब लोग गेहूं पिसवाते नहीं आटा खरीदते हैं, दलहन तिलहन सब कुछ अब हम पैक्ड खरीदते हैं और इसमें मिलावटयुक्त खाद्य पदार्थों का उपभोग हमारी मजबूरी है। इसी कारण से आम जन असाध्य रोगों से ग्रस्त हो रहा है। हम लाख सजग रहें, योग, कसरत सब कुछ करें पर हमारा भोजन अगर मिलावटी और विषाक्त है तो हम अस्वस्थ होंगे ही। अब हालात ऐसे हैं कि खाद्य पदार्थ अगर मिलावटी नहीं तो उसकी खेती ही खतरनाक रासायनों और उर्वरकों से की जाती है और अंततः वह उपज ही हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इस बड़ी समस्या पर एकाएक अंकुश तो नही लग सकता, पर सख्ती और सजगता हमें कुछ हद तक बचा सकती है।

भारत में मिलावट एक अपराध के बजाय व्यावसाय है। और यहां मिलावट के लिये जितने आविष्कार होते रहते हैं वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक हैं। दूध, अनाज, तेल, मसाले, चावल, आटे सब्जियों यहां तक की बड़े ब्रांड के उत्पाद भी इसमें लिप्त हैं। हाल के कुछ सालों में पर्व त्यौहारों में मिलावट का बाजार और बढ जाता है। और यह अंततः देश का स्वास्थ्य ही खराब कर रहा है। विदेशों में ऐसे अपराध को रोकने के लिये सख्त कानून है साथ ही वहां की सरकारें भी सजग रहती हैं। लेकिन भारत में सब कुछ ढुलमुल है यहां जांच और कार्रवाई नुकसान होने के बाद होती है

भारत में कोयले के भविष्य पर मंथन करेंगे विशेषज्ञ

नई दिल्ली : गुजरात के केवडिया के स्टेचू ऑफ यूनिटी में 'कोयला क्षेत्र के लिए भविष्य का मार्ग' विषय पर 17 और 18 फरवरी को चिंतन शिविर हुआ । इसका उद्देश्य कोयला के भविष्य को लेकर रणनीति तैयार करना है। इसमें कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कोयला कंपनियों के सभी सीएमडी शामिल होंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी शिविर का उदघाटन करेंगे। मौके पर कोयले के आयात को खत्म करने और वर्ष 2023-24 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंचने पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जो विदेशी मुद्रा बहिर्गमन का एक बड़ा स्रोत हैं। विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया गया दस्तावेज आगामी महीनों में कोयला क्षेत्र का मार्गदर्शन करेगा।

इन विषयों पर होगा विचार मंथन

- **भारत में कोयले का भविष्य**
- **कोल इंडिया और देश द्वारा एक अरब टन उत्पादन प्राप्त करने की रणनीति**
- **एक अरब टन कोयले के उत्खनन के लिए रणनीति**
- **स्थानीय समुदाय का सहयोग/ टिकाऊ कोयला**
- **कोयला क्षेत्र और व्यापार विविधिकरण में निवेश**
- **भूमि खरीद के वैकल्पिक मॉडल**
- **सेवा (एसईडब्ल्यूए)- सामुदायिक सहायता कार्यक्रम**

ट्रंप की यात्रा से कितना लाभ होगा?

अमेरिका के लिए डेयरी-पोल्ट्री बाजार खोलने की तैयारी हो रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा से पहले कवायद शुरू है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले भारत दौरे पर सीमित व्यापार सौदा हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत ने डेयरी उत्पादों, अमेरिकी चिकन लेग, ब्लूबेरीज और चेरी जैसे उत्पादों के आयात का प्रस्ताव रखा है।

अमेरिका की एक नीति है कि वह कहीं भी किसी भी मित्रता में सबसे पहले अपना वयापारिक हित देखता है। और उसके इस व्यवहार के कारण ही भारतसे उसके संबंध बहुत ही उतार चढाव वाले रहे हैं। याद किजिये बिल क्लिंटन सौहार्द्रपुर्ण माहौल में पीवी नरसिंहराव से वार्ता करते थे और अगले ही दिन सैकड़ो भारतीय कंपिनयों पर अमेरिका में व्यावसाय करने पर रोक लगा देते थे। दरअसल अमेरिका ऐसा अपने हितों को सर्वोपरि रखने के कारण ही करता है। अब भारत का मध्यवर्ग का विशाल बाजार पहले से ज्यादा समृद्ध और सक्षम है तो जाहिर है ट्रंप की पहली प्राथमिकता इस बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिये प्राप्त करने की होगी। इसी कड़ी में चिकन लेग पर टैरिफ (आयात शुल्क) 100% से घटाकर 25% कर दिया गया है लेकिन अमेरिका इसे 10% कराने की कोशिश में है। वहीं, डेयरी उत्पादों के लिए 5% शुल्क और कारोबारी सीमा के साथ भारतीय बाजार खोलने की तैयारी है। हालांकि, सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक भारत में डेयरी उत्पादों के आयात पर रोक है, क्योंकि इससे आठ करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका जुड़ी है।

सूत्रों ने बताया, सरकार अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले-डेविडसन पर भी आयात शुल्कों पर 50 फीसदी कटौती करने जा रही है। हार्ले पर टैरिफ को लेकर ही ट्रंप ने भारत को 'टैरिफ किंग' करार दिया था। आयात शुल्कों में कटौती और अन्य छूट के बाद भारत को उम्मीद है कि अमेरिका विशेष व्यापार दर्जा बहाल कर सकता है, जिसे पिछले साल ट्रंप ने निलंबित कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि व्यापार मुद्दे पर दोनों के बीच आई 'दूरियों' को ट्रंप के दौरे से पहले मिटाने की कोशिश की जा रही है।

एक-दूसरे से क्या चाहते हैं! दोनों देश

आयात शुल्कों में कटौती कर भारत बदले में स्टील और एलुमिनियम उत्पादों पर शुल्कों में छूट चाह रहा है। भारत जीएसपी के तहत निर्यात फायदे की बहाली की उम्मीद भी लगा रहा है। कृषि, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और इंजीनियरिंग क्षेत्र के उत्पादों की अमेरिकी बाजार में अधिक पहुंच की मांग रखी जा रही है। वहीं, अमेरिका भारत में खेती, विनिर्माण, डेयरी उत्पाद, मेडिकल उपकरण और डाटा स्थानीयकरण की बाजार में पहुंच हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने व्यापार घाटे को कम करने की मंशा भी जताई है।

कम हुआ व्यापार घाटा

2018-19 में 52.4 अरब डॉलर का निर्यात तो 35.5 अरब डॉलर का आयात हुआ। 2017-18 में व्यापार घाटा 21.3 अरब डॉलर था, जो 2018-19 में घटकर 16.9 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका से 2018-19 में 3.13 अरब डॉलर की एफडीआई मिली।

भारतीय उद्योग दिग्गजों से मिलेंगे

भारतीय कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ट्रंप 25 फरवरी को भारतीय उद्योग दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। ट्रंप से मुलाकात करने वालों में रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा संस, भारत फोर्ज, महिंद्रा एंड महिंद्रा,मदरसंस समेत कई औद्योगिक घराने शामिल हैं। ये देखना होगा कि ट्रंप इन पर कैसा रूख अपनाते हैं ?

दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है भारत

दुनिया में चीन के बाद भारत अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी देश है। दोनों देशों के बीच 2018 में माल व सेवा व्यापार 142.6 बिलियन डॉलर (10.12 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया था। अमेरिका का भारत के साथ 2019 में 23.2 बिलियन डॉलर (1.65 लाख करोड़ रुपए) का व्यापार घाटा था।

पिछले साल भारत से छीना था विशेष दर्जा

राष्ट्रपति ट्रंप ने 2019 में भारत से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेंज (जीएसपी) का दर्जा छीन लिया था। 1970 के दशक में भारत को यह दर्जा मिला था। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया था, जब भारत ने आयात की जाने वाली अमेरिकी मेडिकल डिवाइस, कार्डियक स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण जैसे उपकरणों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। साथ ही भारत ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी प्रतिबंध लागू किया था। अब ट्रंप की 24-25 फरवरी को होने वाली यात्रा से यह उम्मीद जागी है कि भारत द्वारा टैरिफ में कुछ कटौती करने से जीएसपी दर्जा फिर से मिल सकता है।

रॉबर्ट लाइटहाइजर का दौरा रद्द

ट्रंप के दौर से पहले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर का दौरा रद्द हो गया है। वह वाणिज्य मंत्रालय के साथ सीमित व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए यहां आने वाले थे। लाइटहाइजर के न आने से ट्रंप की मौजूदगी में इस समझौते पर दस्तखत होने को लेकर भी रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और लाइटहाइजर में टेलीफोन पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

22 किमी लंबे रोडशो में शामिल होंगे 50,000 से ज्यादा लोग

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे को यादगार बनाने में गुजरात सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अहमदाबाद की मेयर बिजल पटेल ने बताया कि 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं समेत 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल की उम्मीद है। इसमें 300 संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के स्वंयसेवी भी शामिल होंगे। इस दौरान अलग-अलग राज्यों से आए लोग पारंपरिक पोशाक धारण करेंगे। उन्होंने कहा कि शायद शहर का यह सबसे लंबा रोड शो हो। अहमदाबाद नगर निगम को मिले रूट प्लान के मुताबिक ट्रंप और मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। इसके बाद हवाई अड्डे के पास बने इंदिरा पुल जरिये एसपी रिंग रोड से मोटेरा में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम जायेंगे। स्टेडियम की क्षमता 1.10 लाख लोगों के बैठने की है। यहां दोनों लोगों को संबोधित करेंगे। अब ये देखना है कि इस सबका लाभ भारत को मिलता है या नहीं?

धरती को बचाना है तो लाइफस्टाइल बदलिए

अनिल पी जोशी

ऊर्जा के सीमित उपयोग के लिए आयोजित अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियां आमतौर पर औपचारिकताओं में ही निपटा ली जाती हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने हिस्से के विकास को रोकना चाहता हो। कोई भी कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाना चाहता क्योंकि दुनिया में आज भी कोयला ही उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। कम से कम आने वाले दो-तीन दशकों में हम कोयला का विकल्प तैयार नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि वह चाहे पैरिस का समझौता हो या फिर क्योटो में लिए गए निर्णय, हम उन पर आज तक अमल नहीं कर पाए हैं।

वैसे दुनिया में कोयले की खपत में कुछ हद तक कमी आई है। आज पूरी उर्जा का 42 प्रतिशत कोयले से आता है। अगर दुनिया के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2010 में कोयले पर आया खर्च 134 अरब डॉलर था, जबकि वर्ष 2018 में इस पर 80 अरब डॉलर का खर्च हुआ। पर भारत में तस्वीर नहीं बदली। यहां वर्ष 2010 में कुल खर्च करीब 6 अरब डॉलर था, जो 2018 में 8 अरब डॉलर हो गया। चीन ने जरूर इस मामले में तत्परता दिखाई। वह कोयले की खपत के मामले में काफी आगे था, लेकिन अब उसने इसे नियंत्रित किया है। वहां वर्ष 2010 में कोयले पर 50 अरब डॉलर खर्च हुए लेकिन 2018 तक उसने यह खर्च 30 अरब डॉलर पर ला दिया। जाहिर है चीन ने वैश्विक समझौतों का थोड़ा-बहुत सम्मान किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। वहां 2019 में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जो भी तैयारी हुई वह संतोषजनक नहीं है। भारत में गत वर्ष 1.8 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है, जो वर्ष 2018 की तुलना में कम है। दुनिया के बड़े देशों की ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन उन्हें इसकी भरपाई के रूप में कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए ताकि इससे एकत्रित फंड से संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों को राहत दे सके।

दुर्भाग्य यह है कि बड़े देश इस तरह के योगदान से सीधे कतरा जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब जैसे मुल्क किसी भी तरह की भागीदारी से अब पीछे हट रहे है। अमेरिका और ब्राजील के राष्ट्रपतियों ने तो साफ कह दिया है कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन राष्ट्रों का नेतृत्व वर्ग किसी न किसी उद्योग का हिस्सा होता है या उससे लाभान्वित होता है। इसलिए वह ऐसे निर्णय के साथ नहीं होता जिससे उसके व्यक्तिगत हित पर चोट पहुंचे। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण भारत में ऊर्जा की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसे पूरा करने का सबसे अधिक दबाव कोयला चलित ताप विद्युत संयंत्रों पर है। यही वजह है कि ये ताप विद्युत संयंत्र देश में सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक बन गए हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। भारत कार्बन उत्सर्जन से होने वाले सामाजिक-आर्थिक नुकसान के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर भारत को 86 डॉलर का नुकसान वहन करना पड़ता है। वहीं, 48 डॉलर प्रति टन के नुकसान के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत में विद्युत उत्पादन की मांग पर नजर डालने पर मालूम होता है कि यह प्रतिवर्ष 6.67 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि उत्पादन में वृद्धि 5.78 प्रतिशत की दर से हो रही है। हमारे देश में उत्पादन के 30 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से की बर्बादी बिजली को गंतव्य तक पहुंचाने में ही हो जाती है। यही वजह है कि मांग और उत्पादन में इतने कम फर्क के बावजूद पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती है। भारत विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। भारत सरकार ने देश में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बढ़ते स्तर और पैरिस समझौता द्वारा तय किए गए मानकों को गंभीरता से लेते हुए वर्ष 2030 तक इसमें 33 से 35 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। इसकी पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर निर्भरता को क्रमिक रूप से कम करने का फैसला किया है। सरकार ने मार्च 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा में 175 गीगावाट तक की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें 100 गीगावाट सौर, 60 गीगावाट पवन और 15 गीगावाट अन्य स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य है।आज खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि अगर ऊर्जा की खपत इसी तरह बढ़ती चली गई तो बढ़ते कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण दुनिया में 17 करोड़ लोग सीधे खाद्य असुरक्षा के शिकार हो जाएंगे। इनमें भारत के भी लोग होंगे। जलवायु परिवर्तन का भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। यहां लगभग 65 प्रतिशत कृषि वर्षा पर ही निर्भर है और अगर वातावरण में इस तरह के बदलाव आए तो खेती बुरी तरह प्रभावित होगी।

मौसम का मिजाज :कार्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण वातावरण में तापक्रम बढ़ेगा और इसका सीधा असर ग्लेशियरों पर भी पड़ेगा। एक अनुमान है कि वर्ष 2021 तक अगर हालात यही रहे तो दुनिया में ग्लेशियर तीव्रगति से पिघलेंगे और समुद्र तल में तेजी से वृद्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। सच तो यह है कि अब हमें अपने ही स्तर पर समस्या को समझकर अपने को बढ़ते प्रदूषण से और बिगड़ती परिस्थितियों से बचाना होगा। यह तभी संभव है जब हम अपनी आदतें बदलें और नई जीवन पद्धति को अपनाने के लिए तैयार रहें। हमें वर्तमान की कई सुख-सुविधाएं छोड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। ●

टिड्डियों से निबटने के लिये बनाया मैस्ट्रो एप

फसलों को नष्ट करने वाले कीटों से निपटने के लिए एक नया स्मार्टफोन ऐप विकसित किया गया है। यह जल्द ही उन किसानों की मदद कर सकता है जिनकी फसलों को टिड्डियों के झुंड द्वारा नष्ट किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी टिड्डियों के इस आतंक से बचने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की बात कही है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन की टीम ने मैस्ट्रो नामक विशेष ऐप बनाया है, जो स्मार्टफोन के कैमरे के माध्यम से टिड्डियों और कीटों को पहचान सकता है और उनके जीपीएस लोकेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। यह शोध साइंटिफिक रिपोर्ट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।किसान ऐप की सहायता से टिड्डियां कहा है, उनकी जगह और उनकी संख्या रिकॉर्ड करके यह सुनिश्चित कर सकते है कि फसलों को बचाने के लिए कितनी मात्रा में कीटनाशक का उपयोग किया जाए तथा उन्हें फैलने से कैसे रोका जाए। इसका अगला चरण क्लाउड सर्वर का विकास करना है जिसमें ऐप डेटा को अपलोड किया जाएगा ताकि वास्तविक समय में कीट के स्थान की पहचान की जा सके। इस ऐप की मदद से कीटनाशकों के सटीक उपयोग करके टिड्डी के झुंडों को कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि अफ्रीका के हॉर्न में डेजर्ट टिड्डे का प्रकोप मानवीय संकट को बड़ा सकता है क्योंकि पलायन करने वाले कीटों के झुंड अपने रास्ते में पड़ने वाले फसलों को चोपट कर सकते हैं।

रासायनिक और जैविक हमले से बचाने वाला सेंसर बना

पेन स्टेट एंड नॉर्थईस्ट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण और लोगों की सेहत की निगरानी के लिए एक अति संवेदनशील पहनने योग्य गैस सेंसर विकसित किया है। इससे कहीं भी किसी विषैले रासायनिक और जैविक पदार्थों का पता लगाया जा सकता है, जो आपको व अन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस डिवाइस (सेंसर) का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। जिसमें मानव शरीर से गैसीय बायोमार्कर और वातावरण से प्रदूषकों का पता लगाकर फेफड़ों को नुकसान होने से बचाया जा सकता हैं। जर्नल ऑफ़ मैटेरियल्स केमिस्ट्री में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, यह सेंसर डिवाइस मौजूदा उपकरणों से बेहतर है।

फॉस्फोरस वाली झीलों में जन्मा था जीवन

मुकुल व्यास

पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक संकेत उन झीलों में उत्पन्न हुए थे जहां फॉस्फोरस की अधिक मात्रा थी और इस रसायन की अधिकता इन झीलों में मौजूद कार्बन की वजह से थी। यह नतीजा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने अपनी हालिया स्टडी में निकाला है। इसके लिए इन वैज्ञानिकों ने कैलिफॉर्निया की मोनो लेक और भारत की लोनार झील समेत उन तमाम झीलों से नमूने एकत्र किए, जहां कार्बन की मात्रा अधिक थी।

जीवन के लिए फॉस्फोरस आवश्यक है। यह जीवन के छह अनिवार्य रसायनों में एक है। यह डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यह तत्व बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी वजह से वैज्ञानिक पिछले पचास वर्षों से इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करने के लिए समुचित फॉस्फोरस कहां से आया? नए अध्ययन में दावा किया गया है कि कार्बन बहुल झीलों में फॉस्फोरस के उच्च स्तर ने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को दूसरे रसायनों के साथ बिना जुड़े रहने दिया। इस स्थिति में हुई रासायनिक क्रियाओं में डीएनए और आरएनए के शुरुआती गुच्छे पैदा हुए। अपने अध्ययन के लिए रिसर्चरों ने उन झीलों पर ध्यान केंद्रित किया जो शुष्क माहौल में निर्मित होती हैं।

इन झीलों की वाष्पीकरण दर अधिक होती है जिसकी वजह से उनमें क्षार और लवण की मात्रा ज्यादा होती है। इन झीलों को क्षारीय और लवणीय झीलें भी कहा जाता है और ये सभी सातों महाद्वीप में पाई जाती हैं। रिसर्चरों ने खास तौर पर कैलिफोर्निया की लेक मोनो, केन्या की मगाडी झील और भारत की लोनार झील में फॉस्फोरस की मात्रा पर गौर किया।

उनका कहना है कि इन झीलों में फॉस्फोरस के उच्च स्तर से पता चलता है कि इनमें किसी कुदरती कारण से यह खनिज अधिक मात्रा में जमा होता गया। रिसर्चरों ने पाया कि कार्बन बहुल झीलों में फॉस्फोरस का स्तर समुद्री पानी से 50,000 गुणा अधिक है।

आज ये झीलें जैविक दृष्टि से सक्रिय हैं और इनमें विविध जीव-जंतुओं का वास है। जीव-जंतुओं की मौजूदगी से झील की केमिस्ट्री पर असर पड़ता है। इसलिए शुरुआती झील के पानी की सही समझ बनाने के लिए रिसर्चरों ने प्रयोगशाला में अलग से कार्बन बहुल झीलों के पानी की जांच की। उन्होंने विभिन्न रासायनिक संरचनाओं को लेकर झील के पानी के परीक्षण किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि झीलें किस प्रकार फॉस्फोरस को जमा करती हैं और एक निर्जीव वातावरण में फॉस्फोरस किस प्रकार उच्च स्तर पर पहुंच जाता है?

अध्ययन के सह-लेखक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर डेविड कैटलिंग का कहना है कि झीलों में फॉस्फेट के उच्च स्तर ने ऐसी रासायनिक क्रियाओं को संचालित किया होगा जिनसे फॉस्फोरस आरएनए, प्रोटीनो और फैट के निर्माणाधीन मॉलिक्यूल्स में पहुंचा। हम जानते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। करीब चार अरब वर्ष पहले पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड की बहुलता ने झीलों के निर्माण और उन्हें फॉस्फोरस के अधिकतम स्तर तक ले जाने में मदद की होगी। इसके अलावा कार्बन डाई ऑक्साइड पानी में घुल कर ऐसी अम्लीय परिस्थितियां उत्पन्न करती है जो चट्टानों से फॉस्फोरस को मुक्त करने में सहायक होती हैं।

शुरुआती पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की सक्रियता अधिक थी। अतः कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया करने के लिए पर्याप्त ज्वालामुखीय चट्टानें उपलब्ध थीं। इन्होंने झीलों को समुचित मात्रा में कार्बोनेट और फॉस्फोरस की आपूर्ति की होगी। प्रारंभिक पृथ्वी पर अवश्य ही कार्बन से संपन्न झीलों की अधिकता रही होगी जिनमें फॉस्फोरस के उच्च स्तर ने जीवन की निर्माण प्रक्रिया आरंभ की। प्रसंगवश, इसी अध्ययन के लेखकों ने हाल में किए गए एक दूसरे अध्ययन में कहा था कि कार्बन बहुल झीलें समुचित मात्रा में साइनाइड भी उपलब्ध करा सकती हैं। यह रसायन एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटॉयड के निर्माण में मदद करता है जो प्रोटीनो, डीएनए और आरएनए की निर्माण इकाइयां हैं। ●

पशुओं को धूप में बांधने से मिलती है विटामिन डी

विशेषज्ञों का कहना है कि दिन के समय में पशुओं को खुली धूप में बांधें, जिससे इनका शरीर गर्म रहे तथा विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। नवजात बछड़ियां ठंड के लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसमें ठंड के कारण, श्वासन संबंधित रोग, बुखार तथा डायरिया की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इनका ठंड से बचाव अति महत्वपूर्ण है।

महाशिवरात्रि महोत्सव धुम-धाम से आयोजन हेतु कमिटि का हुआ गठन

रांची : श्री सर्वेश्वर महादेव शिव बारात आयोजन समिति, देवी मण्डप रोड, हेसल, के तत्वावधान में , महाशिवरात्रि महोत्सव धुम-धाम से आयोजन हेतु बैठक श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर हेसल परिसर में सम्पन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से 51 सदस्यीए कमिटि का गठन हुआ जो निम्नलिखित है। मुख्य संरक्षक-लाल संजयनाथ शाहदेव,संरक्षक-सरस सिन्हा, गुरूवचन शर्मा, राज श्रीवास्तव, राजेश्वर सिंह, रविन्द्र सरियार, उदय प्रताप सिंह, उतम यादव, मुख्य आयोजन प्रभारी-बिनोद कुमार साहु,अध्यक्ष-नीरज कुमार,उपाध्यक्ष-मुकेश झा, अंजना प्रियदर्शनी, बबलु सिंह, चन्द्रकान्ता, भगवान सिंह, उपेन्द्र कुमार सिंन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष-दिनेश प्रसाद गुप्ता, सुमित कुमार साहु,महा सचिव- प्रवीण सिंह सचिव-अनिल गुप्ता,सह सचिव-मंटु सिंह, इंदु सिंह, अशोक वर्मा, चेतन साहु, लाल दीपक शाहदेव, मनोज कुमार राय, चेतन साहु, मिडिया प्रभारी-शिव किशोर शर्मा मंत्री- किशोर महापात्रा, विजय कुमार, रतेन्द्र श्रीवास्तव, पिंटु बजाज,कोषाध्यक्ष-अशोक श्रीवास्तव,सह कोषाध्यक्ष- अनिता कुमारी, रिंकी सिंह, पुजा प्रभारी-अविनाश मिश्रा,कार्यकारणी सदस्य-मुन्ना मुण्डा, प्रमोद सिंह, संतोष सहाय, पवन मंडल, चंपा देवी, मीना देवी ।

पंजाब की अपेक्षा झारखंड में मात्र एक फीसदी किसान करते हैं ट्रैक्टर का उपयोग

.....पेज 1 का शेष

राज्य की कृषि में छोटे एवं मझोले किसानों के लिए उपयोगी तकनीकी एवं मशीनरी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। संयुक्त कृषि निदेशक डॉ महालिंगम शिवा ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं 10 प्रतिशत अनुदान से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पूरा लाभ लेने को कहा।

मौके पर उप कृषि निदेशक मुकेश सिन्हा, डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद, डीन फॉरेस्ट्री डॉ एमएच सिद्दीकी एवं निदेशक समेति सुभाष सिंह ने भी अपने विचार रखें। स्वागत करते हुए कृषि अभियंत्रण विभाग के अध्यक्ष प्रो डीके रूसिया ने कृषि मशीनरी के उपयोग से 30-35 प्रतिशत कृषि लागत में कमी एवं कृषि अभियंत्रण की नई तकनीकों को अपनाकर किसानों को अधिकतम लाभ लेने के बारे में बताया। धन्यवाद डॉ उत्तम कुमार ने किया।

मेले के आयोजन में आईसीएआर परियोजना प्रभारी डॉ उत्तम कुमार, डॉ मिंटू जॉब, डॉ प्रमोद रॉय, डॉ इरफान अंसारी के अलावा कृषि अभियंत्रण विभाग के छात्र झ छात्राओं एवं कैलाश रॉय ने प्रमुख योगदान दिया। मेले में रांची, रामगढ, खूंटी, हजारीबाग, गुमला एवं लोहरदगा के अलावा जेएमटीटीसी, जेटीडीएस, जेएसएलपीएस एवं पालकोट किसान प्रोड्यूसर के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने आईसीएआर की अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं की किसानोंपयोगी कृषि उपकरणों एवं यंत्रो का प्रत्यक्षण एवं रख-रखाव, कृषि में प्लास्टिक का उपयोग, माइक्रो (सूक्ष्म) सिंचाई, नवीकरण उर्जा एवं फसल कटाई उपरांत तकनीकों को देखा। किसान गोष्ठी में विभाग के वैज्ञानिकों ने प्रो डीके रूसिया की अध्यक्षता में मौजूद किसानों की शंका का समाधान बताया।

अनुशासन ही देश को महान बनाता है: सुप्रियो भट्टाचार्या

संवददाता/रांची : डी.ए.भी शिक्षादीप कमड़े में वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन धुमधाम से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्व समाजसेवी जयप्रकाशनगर महाबीर मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने किया। महोत्सव का उदघाटन मुख्यअतिथि झामुमो के प्रधान महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या एवं विशिष्ट अतिथि छात्र क्लब ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा, संरक्षक नामधारी प्रसाद, विद्यालय के निदेशक शिवनन्दन पाठक, समाजसेवी सतीश द्विवेदी, विश्वजीत भट्टाचार्या, रितेश द्विवेदी, देशबंधु आई.टी.आई के प्राचार्य अविनाश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग भोजपुरी, नागपुरी, नाटक, चुट-कुला, फैंसी ड्रेस, फिल्मी गीत, प्रस्तुत कर अतिथियो का मनोरंजन किया। विद्यालय के निदेशक शिवनन्दन पाठक ने कहा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन से बच्चो का मानसिक एवं बौधिक विकास होता है। मुख्यअतिथि सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा अनुशासन हि देश को महान बनाता है। आप डॉक्टर, इंजिनियर, नेता, अभिनेता आदि बने तो राज्य एवं विद्यालय परिवार का नाम रौशन होगा। उन्होने कहा मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य कि कामना करता हुँ। कार्यक्रम का समापन अतिथियो द्वारा पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य अनिल कुमार राय ने किया। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में कुणाल कौशल पाठक, प्रभाश गौरव, लालमोहन पाठक, अविनाश गौरव, संगीता कुमारी, अंजली पाठक आदि ने महत्वपुर्ण भुमिका निभाई।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने किया पर्यटन विभाग के कैलेंडर 2020 का विमोचन

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई कैलेंडर और टेबल कैलेंडर 2020 का विमोचन किया। झारखंड पर्यटन विभाग का वर्ष 2020 का कैलेंडर इको टूरिज्म एवं झारखंड की कला संस्कृति पर आधारित है। कैलेंडर में झारखंड के इको टूरिज्म व कला संस्कृति से जुड़ी फोटोग्राफ को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, पर्यटन विभाग के सचिव राहुल शर्मा, निदेशक पर्यटन विभाग संजीव बेसरा, जेटीडीसी के अनमोल सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीएमडी सीसीएल को मिला 'एनर्जी एंड इनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड'

संवाददता

रांची :द एनर्जी एंड इनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय (15 से 17 फरवरी) 10वां वर्ल्ड पेट्रो कोल कांग्रेस एंड वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट में सेंट्रल कोल्फील्डस लिमिटिड (सीसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह को 'एनर्जी एंड इनवायरनमेंट फाउंडेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सीएमडी गोपाल सिंह के नेतृत्व में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम उर्जा एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, एवं नीति आयोग के सहयोग से प्रतिवर्ष द एनर्जी एंड इनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है।

यह अवार्ड माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान ने सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह को प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एवं अन्य देशों के प्रतिनिधिगण सहित अन्य संस्थानों के अतिथिगण उपस्थित थे।

इस अवसर विशेष पर सीएमडी गोपाल सिंह ने माननीय मंत्री महोदय का अभार व्यक्त करते हुये कहा कि यह अवार्ड हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि कोयला एवं खान मंत्रालय एवं कोल इंडिया का सहयोग निरंतर मिलता रहा है जिसके कारण कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रहा है।

गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीसीएल न सिर्फ कोयला उत्पादन, उत्पादकता, प्रेषण में नई उंचाईयों को छू रहा है बल्कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी सतत कार्य कर रहा है। ज्ञातव्य हो कि एक जिम्मेदार सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका निभाते हुए सीसीएल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की दिशा मे ठोस कदम उठाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक 45 हेक्टेयर भूमि पर 01 लाख 12 हजार 5 सौ पौधे लगाकर सघन वनीकरण किया जा चुका है। सीसीएल का अगले पांच वर्षो में लगभग 300 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर 80 लाख से अधिक पौधे लगाकर सघन वनीकरण करने की योजना है।

सुदामडीह में गंगा मेला एवं फुटबॉल मैच का आयोजन

संवाददाता

रांची: पंचपरगना में प्रसिद्ध गंगा मेला का आयोजन सुमानडीह ग्राम में किया गया। मेले में फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। इसमे कुल आठ टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम गुमला को नगद ईनामी राशि एक लाख ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह रूपये दी गयी। उपविजेता फुटबॉल टीम पुरलिया को पच्चासी हजार रुपये नगद दी गयी।आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। मैच में कमेंट्री मृत्युंजय महतो ने किया। मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर उलगुलान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रामदुर्लभ सिंह ,विशिष्ट अतिथि के रूप में सजल कुंडू , कृष्णा लोहरा उपस्थित रहे। मंच संचालन ग्राम प्रधान दलगोविंद सिंह मुंडा ने किया। कवि मुक्तिपद महतो,गांव के योगेश्वर महतो, भीम महतो , सत्यनाराण महतो, योगेश्वर, सूरेश महतो, राजेन्द्र महतो, विन्देश्वर महतो, प्रो. लोहरा महतो, शिक्षक लखीदास महतो, महावीर महतो, नटवर महतो , सन्तोष महतो, दुबराज महतो, नागेश्वर महतो, मधसूदन महतो, सृष्टिधर महतो भी मौजूद रहे। मेले में रात्रि में छऊ नृत्य का भी आयोजन किया गया।

गुरूकृपा पब्लिक स्कूल ने दी शहीदों को श्रद्धाजंली

रांची : 14फरवरी को जम्मु-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में देश के शहीद हुए सी. आर. पी . एफ के वीर जवानो के पुण्यतिथि पर रातु रोड, पिस्कामोड़ स्थित गुरूकृपा पब्लिक स्कुल में शोकसभा का आयोजन कर उन्हें अश्रुपुरीत नमन व भावपुर्ण श्रद्वांजली अर्पित कि गई। इस शोक सभा में मुख्यरूप से अवकाश प्राप्त नेवी अफसर राजीव रंजन सिंह, छात्र क्लब के अध्यक्ष शिवकिशोर शर्मा, संरक्षक नीलम शर्मा, विद्यालय के संस्थापिका नीतु सिंह, निदेशक रत्नेश सिंह सोलंकी, प्राचार्या कल्याणी सिंह, शिक्षिका सुमन कुमारी, रश्मि प्रिया, एवं बच्चे शामिल हुए। पायल मैम एवं विक्की मैम ने शहिदों के यादगार में देशभक्ति गीत के गंगा बहाऐ। नीतु सिंह ने कहा हम सभी को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। शिव किशोर शर्मा ने शहिदों के वीरगाथा याद करते हुए कहा वीर शहिदों का बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। राजीव रंजन सिंह ने बच्चो को वीर सैनिको के ईतिहास को बतलाया। इसके पुर्व विद्यालय परिवार में शहिदो के स्मरण में पौधारोपण किया।

दक्षिण पूर्व रेलवे महिला हॉकी टीम बनी उपविजेता

रांची : 12फरवरी को मण्डल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ ने दक्षिण पूर्व रेलवे की महिला हॉकी टीम जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित भारतीय रेल महिला हॉकी लीग वर्ष 2019-20 की उपविजेता रही, उन्हें इस लीग मे द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लीग का आयोजन 31.01.2020 से दिनांक 05.02.2020 तक किया गया था। जिसमें भारतीय रेल के कुल 8 टीमों ने भाग लिया इन आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया था ` लीग चरण के बाद फाइनल मैच दक्षिण पूर्व रेलवे महिला हॉकी टीम एवं उत्तर रेलवे की महिला हॉकी टीम के साथ खेला गया जिसमें उत्तर रेलवे की महिला हॉकी टीम ने 2-1 से विजय प्राप्त की । इस लीग में प्रथम स्थान उत्तर रेलवे को प्राप्त हुआ, द्वितीय स्थान दक्षिण पूर्व रेलवे, तृतीय स्थान रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला एवं चतुर्थ स्थान मध्य रेलवे को प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर अपर मण्डल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) श्री अजीत सिंह यादव, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक सह मण्डल क्रीड़ा अधिकारी श्री अवनीश, वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी श्री माणिक शंकर तथा सहायक कार्मिक अधिकारी श्री ऋषब सिन्हा उपस्थित थे।

ग्रामीणों की सजगता से कटने से बचा कल्प वृक्ष

सिदाम महतो

रांची/बुण्डू: झारखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य से सड़क किनारे के हजारों पेड़ों को काट दिया गया ।रांची - टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे-किनारे के कई वृक्ष को भी काटा गया। मार्ग में आने वाली कांची नदी के किनारे पोड़ाडीह में एक वृक्ष को जिन्दा छोड़ दिया गया। पास के बरगद, पीपल वृक्ष को काट दिया गया।जीवित पेड़ पर एक प्लेट लगाया गया है, उस पर लिखा हुआ है- "दुर्लभ वृक्ष कल्पतरु, वृक्ष लगानेवाले पर्यावरणप्रेमी वृद्ध हो चुके महानन्द साहू हैं।

कल्पतरु का उल्लेख वेद और पुराणों में मिलता है।हिन्दू मान्यताओं के अनुसार यह मन जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है, वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों के अनुसार समुद्रमंथन के 14 रत्नों में से एक कल्पवृक्ष की भी उत्तपत्ति हुई थी।इस वृक्ष को इंद्र ने सुरकानन वन में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह हजारों साल तक जिन्दा रहने वाला वृक्ष है। वृक्ष लगानेवाले महानन्द साहू बुण्डू प्रखण्ड के हेठ कांची निवासी हैं। उनकी उम्र अभी 80 साल है। 1960 के दशक से लगातार मुखिया के रूप में समाज सेवा से जुड़े रहे।।वर्तमान में वे अपने बेटों के साथ पोड़ाडीह में रहते हैं। पर्यावरणप्रेमी महानन्द जी गांव की जमीन पर कई बहुमूल्य पेड़ लगाकर बगीचा का निर्माण भी किए हैं। कल्पवृक्ष पेड़ लगाने के बारे में वे बतातें है कि लगभग 17 साल पहले हम बंगाल से कुछ पौधा लेकर आए थे। सड़क किनारे छाया हो इस ख्याल से उन पौधों को रोप दिए थे। कुछ तो गाड़ी की चपेट में बर्बाद हो गए। यह पेड़ जिन्दा रह गया।उस समय तो मालूम भी नही था कि यह कल्पवृक्ष का पौधा है। इस वृक्ष में जून माह में फूल आते हैं जो कमल फूल के समान खिलते हैं। फूल देखकर इस वृक्ष को लोग गाछ कमल कहने लगे ।सड़क चौड़ीकरण के कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने कल्पवृक्ष का फ़ोटो दिखाकर कहा कि यह भी कल्पवृक्ष है। बाद में वन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वालों ने भी कहा कि यह कल्पवृक्ष का ही पौधा है। इस तरह यह पेड़ कटने से बच गया।

कल्पवृक्ष भारत में दुर्लभ वृक्ष की श्रेणी में आता है। भारत में कुछ ही जगह में यह वृक्ष है। झारखण्ड के डोरंडा(रांची) में भी कल्पवृक्ष है। अब कांची नदी के किनारे(पोड़ाडीह) में भी एक कल्पवृक्ष हो गया।

रेलवे महाप्रबंधक संजय कुमार महंती ने किया हटिया ओरगा सेक्शन का निरीक्षण

रांची :14 फरवरी को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार महांति ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के प्रधान मुख्य शाखा अधिकारियों के साथ रांची मंडल के हटिया - ओरगा रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मण्डल रेल प्रबन्धक रांची नीरज अंबष्ठ एवं शाखा अधिकारी उपस्थित थे । इसके तहत गोविंदपुर रोड और बलसिरिंग के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के चलने का परीक्षण किया गया। महाप्रबंधक ने मुख्य मंत्री झारखण्ड हेमंत सोरेन से भी मुलाक़ात की तथा झारखण्ड राज्य मे कार्यरत रेलवे की परियोजनाओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक से विभिन्न स्टेशनों पर जनप्रतिनिधियों, यात्रियों तथा स्थानीय नागरिकों से यात्री सुविधा से संबंधित विषय पर चर्चा की महाप्रबंधक ने और बेहतर यात्री सुविधाएं सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। इस दौरान महाप्रबंधक से विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने ओरगा मे भेट की तथा सांसद संजय सेठ , सांसद लोहरदगा सुदर्शन भगत, विधायकहटिया नवीन जायसवाल, विधायक सिसई जीगा सुसारन होरो, विधायक तोरपा कोचे मुंडा ने हटिया रेल्वे स्टेशन मे महाप्रबंधक से मुलाक़ात की और रांची रेल मण्डल के विकास पर चर्चा की । महाप्रबंधक ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से आग्रह किया कि रेल परिचालन में संरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहें। महाप्रबंधक ने संतुष्टि व्यक्त की और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार के लिए दिशा निर्देश दिए ।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जयंती मनाई गई

रांची: छात्र क्लब के तत्वावधान में बुधवार 12 फरवरी को स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला विकास मंच के महामंत्री प्रिया कुमारी गुप्ता, विशिष्ट अतिथि भाजपा ग्रामीण राँची जिला ओ.बी.सी. मोर्चा के मंत्री अरूण प्रसाद, समाजसेवी संजय उरांव, पिस्कामोड़ गुरूद्वारा के मुख्यग्रन्थी बाबा बख्शीष सिंह मौजूद थे। मौके पर क्लब के संरक्षक सुनिता चैधरी, अंजना प्रियदर्शनी, सहित मुन्नी उराँव, प्रेम कुमार सिंह, शुभम कुमार यादव, अपना कुजूर ने सराहनीय भूमिका निभाई।

पीएम किसान के लाभार्थियों को मिलेगा केसीसी

संवाददाता

- **25 फरवरी तक विशेष अभियान**
- **अब इसके दायरे में पशुपालन एवं मत्स्य पालन में शामिल**
- **सीओ को लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर कागजात उपलब्ध कराने का निदेश**
- **ग्रामसभा का आयोजन कर दी जायेगी जानकारी**

प्रेस कांफ्रेस में जानकारी देते अधिकारी

रांची :12 फरवरी 2020 को अनुमंडल पदाधिकारी, सदर रांची लोकेश मिश्रा ने केसीसी ऋण से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत सरकार ने देश के सभी योग्य किसानों को केसीसी के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए एक अभियान चलाया है। यह अभियान जिले में 8 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2020 तक मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इसमें पीएम किसान योजना के उन सभी लाभार्थी जिन्हें केसीसी नहीं दिया गया है, उन्हें केसीसी से आच्छादित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आईबीए ने इस अभियान में केसीसी प्राप्त करने के लिए एक पेज का सरलीकृत आवेदन तैयार किया है, जो सभी बैंकों के वेबसाइट, मंत्रालय के वेबसाइट (www.agricoop.gov.in) और पीएम किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर उपलब्ध है। उन्होंने पीएम किसान के लाभार्थियों से अपने बैंक जहां उनका पीएम किसान खाता है वहां पहुंचकर एक पेज का आवेदन, जमीन के दस्तावेज और बोये जाने वाले फसल का विवरण देकर केसीसी इस अभियान अवधि के दौरान प्राप्त करने का अनुरोध किया।

सीओ/बीडीओ को दिये गये निदेश

किसानों को बैंक में देने के लिए जो भी आवश्यक कागजात चाहिए इसके लिए सभी सीओ को निदेश दिया गया है कि इस योजना का लाभ लेने आनेवाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर कागजात मुहैया करायें। साथ ही सभी बीडीओ को भी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है। जेएसएलपीएस के सखी मंडल को भी इसकी जानकारी दी गयी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाये गये विशेष अभियान में पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को आठ से 25 फरवरी तक केसीसी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि तीन तरह के केसीसी दिये जा रहे हैं। पहला, जो नये किसान हैं। दूसरा, जो किसान पहले से केसीसी ले चुके हैं और अब इनएक्टिव हैं उनको एक्टिवेट करने का प्रयास किया जायेगा। इसमें लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो लिमिट भी बढ़ाया जायेगा। तीसरा, इसमें अब फिशरीज और डेयरीज को शामिल किया गया है। 1.60 लाख का केसीसी लोन लेते हैं तो कुछ भी सिक्युरिटी की जरुरत नहीं।

उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों का रजिस्टेज्शन हुआ है, उनकी सूची हमें मिल गयी है, जिसे सभी बैंकों को दे दिया गया है, आवेदनों की मैपिंग कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आच्छादित करने का प्रयास किया जायेगा। सभी संबंधित विभाग मिलकर जागरुकता फैलायेंगे और एप्लीकेशन जेनरेट करेंगे। ब्रांच लेवल पर बैंकों को कहा गया है कि पंचायत स्तर पर वो कम से कम एक या दो कैंप करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर मेगा कैंप का आयोजन किया जायेगा ताकि आसपास के लोग केसीसी का आवेदन दे सकें। बैंकों को किसानों से प्राप्त आवेदनों को 12 दिनों के अन्दर केसीसी देने का निर्देश दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीडीएम नाबार्ड रांची एसएस राम, जिला कृषि पदाधिकारी, रांची अशोक कुमार सिन्हा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रांची मनोज कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी अरुप कुमार चौधरी, डीपीएम जेएसएलपीएस सुश्री शांति मार्डी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी गिरीश कुमार उपस्थित थे।

BOOK INDIA
DEALS IN SCHOOL BOOKS & STATIONARY
BRANDED BOOK REASONABLE PRICE
LEADING PUBLISHERS
- Top High Quality Books
- C.B.S.E., NCERT,ICSE & JAC Board
- 365 Days Services

SPECIALIST IN Pvt. School Books/Play School Books/Childrens Books

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध
Sahay Compound, St. Anne's Girls School Lane, Tharpakhna, Ranchi Ph. : 9199365691,7050112727,0651-6522703

फोटो न्यूज

बैलगाड़ी से मिट्टी ढोकर ग्रामीणों से बनाया सुदाम डीह का गंगा मैदान

सिदाम

कुदरत के वरदान से और लोगों के मेहनत से 'गंगा मैदान' का निर्माण हुआ। नदी के द्वारा लाई गयी मिट्टी और ग्रामीणों के द्वारा बैलगाड़ी से लाई गयी मिट्टी से खूबसूरत मैदान की नींव पड़ी।भारत में हर नदी को गंगा का ही रूप माना जाता है। इस वजह से इस मैदान का नाम 'गंगा मैदान' रखा गया है।1992 में निर्मित इस मैदान में पंचपरगना प्रसिद्ध 'गंगा मेला' का आयोजन इसी मैदान पर किया जाता है।फ़रवरी महीना का दूसरा रविवार जब ठण्ड अपने पड़ाव पर और गर्मी के आने की आहट होती है। तब यहां लोग फुटबॉल खेल के साथ छोऊ नृत्य का आनन्द उठाते हैं।इस आयोजन में सुमानडीह ग्राम के साथ सुमानडीह पंचायत के समस्त ग्रामीणों का अहम योगदान रहता है। साथ यह मैदान प्रखण्ड मुख्यालय बुण्डू से लगभग 12 पहले है। कल -कल बहती कांची नदी का दृश्य, नजदीक के चन्चालू पहाड़ की चोटी का शानदार नजारा इस मैदान से देखा जा सकता है । कई नागपुरी एल्बम की शूटिंग में यह मैदान ,यहां का दृश्य कैमरे में कैद हो चुका है।

बंद हो जायेगी 107 साल पुरानी रेल लाइन

- उत्तर प्रदेश के दुधवा नैशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन होगी बंद
- रेलवे अब मीटर गेज लाइन को एक धरोहर के रूप में संरक्षित करने की योजना बना रहा है। एक अधिकारी ने कहा, 'हम दुधवा आने वालों के लिए एक टॉय ट्रेन शुरू कर सकते हैं, जो जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।'
- नानपारा और मैलानी के बीच जंगलों और खेतों से होकर गुजरने वाली 171 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बंद करने का फैसला
- जंगली जानवरों और जंगल के संरक्षण पर उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने लिया फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के दुधवा नैशनल पार्क से होकर गुजरने वाली 109 साल पुरानी रेलवे लाइन बंद होने जा रही है। नानपारा और मैलानी के बीच 171 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग जो जंगलों और खेतों से होकर यात्रियों को ले जाता है, वह लखीमपुर-मैलानी ब्रॉड गेज मार्ग के इस महीने के अंत में खुलने के बाद बंद हो जाएगा। ऐसा जंगली जानवरों और जंगल के संरक्षण पर उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद किया जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक संजय पाठक ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं में 100 से अधिक जानवर मारे गए हैं। इनमें हिरण, बाघ, हाथी, मगरमच्छ, गैंडे और स्लॉथ बेयर शामिल हैं। दूसरी ओर, नानपारा और मैलानी के बीच पड़ने वाले गांवों में रहने वाले 30 लाख से अधिक लोग रेल लाइन के बंद होने से प्रभावित होंगे। इन ग्रामीणों के लिए, रेलवे लाइन उनकी एकमात्र लाइफलाइन है जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ती है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआ-रओ) पंकज सिंह ने कहा कि दुधवा से होकर जाने वाले मार्ग कई भागों में पूरे हो चुके हैं।

14 फरवरी को स्वामी मुक्तरथ जी के वेबसाइट www.muktrathyoga.com का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति एवं रांची के बड़े एवं प्रतिष्ठित पत्रकार हरिवंश जी ने किया। इस अवसर पर कई गण्य मान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे

शिव बारात आयोजन महासमिति पदाधिकारी संजय सेठ से मिले

रांची : 15 फरवरी को शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर, रातु रोड के अध्यक्ष राजेश साहू, कार्यकारी अध्यक्ष नन्दकिशोर सिंह चंदेल, वरीय उपाध्यक्ष सुभाष सिन्हा, बादल सिंह, अतिराज सिन्हा, संगठन मंत्री दिलीप गुप्ता, सचिव राजकुमार तनेजा, संजय अम्बष्ठा, दीपक नंदा, भोलू सिंह, मिडिया प्रभारी शिवकिशोर शर्मा, अक्षय पाठक आदि पदाधिकारी शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर, रातु रोड के मुख्यसंरक्षक सह सांसद राँची संजय सेठ, संरक्षक सी.पी.सिंह, आशा लकड़ा, सूरज भान सिंह, रमेश सिंह से मिलकर गुलदस्ता भेंट की एवं धुमधाम से शिव बारात आयोजन हेतु विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक संजय सेठ एवं सभी संरक्षकों ने उपस्थित होकर हर संम्भव मदद के लिए भरोसा दिया।

चीनी उत्पादन में बड़े बदलाव की संभावना नहीं : इस्मा

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने कहा कि 2019-20 के लिए भारत के चीनी उत्पादन अनुमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान भी 2.6 करोड़ टन उत्पादन रहने का ही अनुमान है। इस्मा के अध्यक्ष विवेक पिट्टी ने कहा, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे अनुमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखती है। तीन साल के निचले स्तर पर रह सकता है उत्पादन

उन्होंने कहा कि 2018 में सूखे की वजह से देश में चीनी उत्पादन प्रभावित हुआ था, जिसने किसानों को गन्ना उत्पादन करने के लिए मजबूर किया। 2019 में बाढ़ ने फसल को नुकसान पहुंचाया। इस कारण 2019-20 में चीनी उत्पादन 21.6 फीसदी घटकर 2.6 करोड़ टन रह सकता है, जो तीन साल का सबसे निचला स्तर है। हालांकि, इस दौरान महाराष्ट्र में उत्पादन बढ़कर 65 लाख टन रह सकता है, जो 62 लाख टन उत्पादन के अनुमान से ज्यादा है। व्यापार मंडल का अनुमान है कि 2019-20 में 8 लाख टन से अधिक गन्ने को एथेनॉल में बदला जाएगा। यह पिछले सत्र के मुकाबले पांच लाख टन से ज्यादा है। वहीं, इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा का कहना है कि भारत में गन्ने का काफी स्टॉक है, जिससे एथेनॉल बन सकता है। क्षमता बढ़ने के साथ गन्ने को अधिक मात्रा में एथेनॉल में बदला जा सकता है। वर्तमान में यह क्षमता 3.5 अरब लीटर है, जबकि जरूरत 5.11 अरब लीटर की है। है।

निर्यात नीति में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

इस्मा का कहना है कि देश के चीनी निर्यात नीति में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले साल सरकार ने अपना स्टॉक घटाने के लिए 2019-20 के लिए 10,448 रुपये प्रति टन चीनी निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दी। इस पर प्रमुख चीनी उत्पादक देशों ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका मानना था कि भारत सरकार की सब्सिडी नीति से दुनियाभर में चीनी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह आधारित रिफाइनरी चलाने वाली दुबई की अल खलीज शुगर ने भी इस सब्सिडी पर आपत्ति जताई थी।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने झारखंड से प्रकाशित होने वाले एकमात्र पर्यावरण आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र ग्रीन रिवोल्ट को देखा और इस प्रयास के लिये प्रसन्नता जाहिर की

पानी विवाद में सबसे ज्यादा हत्यायें गुजरात में

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2018 के अपराधों का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें पानी को लेकर हुए विवादों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2018 के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक 2017 में पानी को लेकर 432 आपराधिक घटनाएं हुई, जो 2018 में बढ़कर 838 हो गई। इसके अलावा 2018 में पानी की वजह से 92 लोगों की हत्याएं कर दी गई।एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में पानी विवाद को लेकर जिन राज्यों में हत्या के मामले दिल्ली सहित 10 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। हत्या के सबसे अधिक मामले गुजरात में 18 हत्या के मामले दर्ज किए, जबकि बिहार में 15, महाराष्ट्र में 14, उत्तर प्रदेश में 12, राजस्थान और झारखंड में 10-10, कर्नाटक में 4, पंजाब में 3, तेलंगाना में 2, मध्य प्रदेश में 2, तमिलनाडु में 1 और दिल्ली में 1 हत्या का मामला दर्ज हुआ।

बढते तापमान से बीज खाने वाले कीटों में वृद्धी

राजन कुमार

इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल द्वारा किए गए शोध में पेड़ों की मार्स्टिंग और उनके बीजों को खाने वाले कीटों के बीच जटिल संबंधों पर जलवायु के प्रभाव का पता चला है।

मार्स्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ साल-दर-साल अलग-अलग मात्रा में बीजों का उत्पादन करते हैं। कई पेड़ों की प्रजातियों में यह विशेषता पाई जाती है, जिनमें ओक, बीच, चीड़ और स्प्रेज़ शामिल हैं। यह प्रक्रिया फायदेमंद होती है क्योंकिअकाल के वर्षों ' के दौरान, बीजों को खाने वाले जीव जैसे पतंगे आदि भूखे रह जाते है, जिसके कारण उनकी संख्या कम हो जाती है। जबकि बम्पर वर्षों' में, बीज का उत्पादन इतना अधिक होता है कि यह बीजों को खाने वाले कीटों को भरपूर भोजन प्रदान करता है। बीज का उत्पादन अधिक होने के कारण इनके जमने की संभावना बढ़ जाती है जिससे ये अगली पीढ़ी के पेड़ों के रूप में उग सकते है।हालांकि, नेचर प्लांट्स में प्रकाशित बीच ट्री सीड प्रोडक्शन के एक अध्ययन में पाया गया कि गर्म तापमान के कारण बीज उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ, साल-दर-साल बदलाव हो रहा है। विशेष रूप से अकाल के वर्षों में बीज उत्पादन में कमी आई है। इस प्रकार बीज उत्पादन में जलवायु के प्रभाव से होने वाली वृद्धि से बीज खाने वाले जीवों को फायदा होता है, इस-ाका पेड़ पौधों को किसी तरह का कोई लाभ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंसेज के सह-अध्ययनकर्ता डॉ. एंड्रयू हैकेट-पैन ने कहा कि यह अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बीच के पेड़ों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा हैं। क्या जलवायु परिवर्तन से पेड़ों के बीज उत्पादन में वृद्धि हो रही है? लेकिन हमने देखा कि बीज उत्पादन में वृद्धि से मोथ लार्वा नामक जीव को लाभ हो रहा है इसकी बीज खपत की क्षमता लगभग पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ अधिक बीजों का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनके बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के डॉ. जोनाथन लेगर्ड ने कहा कि, इस शोध में, हमने चार दशकों तक निगरानी किए गए डेटा का उपयोग किया हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जलवायु परिवर्तन ने सबसे व्यापक पेड़ों में से एक के प्रजनन को कैसे प्रभावित किया है। हमने देखा कि उस समय की अवधि में बीज उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इस उत्पादन का फायदा केवल बीज खाने वाले कीटों को हुआ। हालांकि, दुनियां भर में खास-ाकर ब्रिटेन के बीच के पेड़ों में 'अधिक और कम' बीज उत्पादन पैटर्न से कीट आबादी में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, हमने लार्वा द्वारा खाए जाने वाले बीजों के प्रतिशत में बहुत अधिक वृद्धि देखी है। यह 1980 के दशक में लगभग 1 फीसदी थी जो हाल के वर्षों में बढ़कर 40 फीसदी तक हो गई है। इस वृद्धि में बढ़ते तापमान की अहम भूमिका है।

कम हुई नैनी झील की गहराई, अस्तित्व पर संकट के आसार

पिछले वर्ष नवंबर में इसरो की टीम ने झील का परीक्षण किया था, 10 फरवरी को इसकी रिपोर्ट नैनीताल जिला प्रशासन को सौंपी गई है

नैनी झील की मौजूदा स्थिति वैज्ञानिकों के लिए चिंता की वजह बनी हुई है। नैनीताल में चल रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते झील में गाद का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद शहर में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं जो झील की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अब झील के संरक्षण में तकनीकी मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद आगे आया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक मूल समस्या हल नहीं होती, नैनीताल की वहन करने की क्षमता से अधिक हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगती, नैनी झील को उसके पुराने स्वरूप में लौटाना संभव नहीं होगा।

जाड़े में भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग

एजेंसियां

उत्तराखंड में 29 डिग्री पहुंचा तापमान, जंगलों में अभी से लगने लगी आग

- **पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तराखंड में फरवरी के पहले पखवाड़े में इतना उच्च तापमान नहीं पहुंचा, जिसे जलवायु परिवर्तन का हिस्सा माना जा रहा है**
- **उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी के ऊंचाई वाले जंगलों में 14 फरवरी की रात से दिख रही हैं आग की लपटें।**

उत्तराखंड वन विभाग का फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो गया है। यह सीजन मानसून आने तक यानी लगभग 15 जून तक चलेगा। लेकिन, इस बार औपचारिक फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। जोशीमठ के पास उर्गम घाटी में 12 और 13 फरवरी को लगातार दो दिन तक जंगल में आग सुलगती रही। केदारनाथ घाटी में तुंगनाथ के पास के जंगलों में 14 फरवरी से आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग की इन घटनाओं से वन विभाग की चिन्ताएं बढ़ गई हैं। हालांकि विभाग ने दावा किया है कि जंगलों की आग से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू हो जाने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, लेकिन आग की एक-दो घटनाओं से निपटने में दो-दो दिन लग जाने से अंदाजा लगाया जाता है कि पीक सीजन में जब एक ही दिन में सैकड़ों जगहों पर वनों में आग लग जाती है, तब वन विभाग इससे कैसे निपटेगा। इस बार दिसम्बर और जनवरी के महीने में अच्छी बारिश और बर्फबारी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वनों में आग की घटनाओं में कमी आएगी और आग लगने घटनाएं पिछले वर्षों की तुलना में देर से शुरू होंगी, लेकिन फरवरी पहले पखवाड़े में अचानक तापमान में हुई जबरदस्त बढ़ोत्तरी और चमोली व रुद्रप्रयाग जिलों में आग की घटनाओं ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

पिछले दस वर्षों में पहली बार फरवरी के पहले पखवाड़े में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। बीते 13 फरवरी को देहर-ादून में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वर्ष 2010 के बाद फरवरी के महीने में दो ही ऐसे मौके आए हैं, जब अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। लेकिन, दोनों बार ऐसा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हुआ। 23 फरवरी, 2018 को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और 28 फरवरी, 2010 को 29.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फरवरी महीने में देहरादून में अब तक का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 2006 में 25 फरवरी को दर्ज किया गया था। देहरादून में मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक बिक्रम सिंह मानते हैं कि फरवरी के पहले पखवाड़े में तापमान में यह बढ़ोत्तरी अप्रत्याशित है, लेकिन वे कहते हैं कि अगले दिनों में तापमान में कमी दर्ज होगी। इसके बावजूद वे सलाह देते हैं कि वन विभाग को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है।

पर्यावरणविद् रमेश पहाड़ी कहते हैं कि बर्फबारी के कुछ दिन बाद ही कई जगह जंगलों में आग की लपटें नजर आने लगी हैं। यह बेहद चिन्ताजनक स्थिति है। वे कहते हैं कि यदि समय रहते सभी बंदोबस्त नहीं किये गये तो स्थितियां 2016 से भी बदतर हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि 2016 में उत्तराखंड के जंगलों में आग की अब तक की सबसे ज्यादा और सबसे भयावह घटनाएं घटी थी। उस वर्ष कुल 4,538 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ गया था। वर्ष 2010 से 2019 तक राज्य में कुल 19,945 हेक्टेयर वन आग से स्वाहा हुए, यानी कि हर साल औसतन 1994 हेक्टेयर वनों में आग लगी है।

वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वनों की आग से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वन विभाग में फॉरेस्ट फायर के नोडल अधिकारी बीके गांगटे ने दावा किया है कि वनों की आग से निपटने के लिए 40 मास्टर कंट्रोल रूम और 175 वॉच टावर बनाये गये हैं। इसके अलावा 1437 क्रू स्टेशन बनाए गये हैं, जिनमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। उनका दावा है कि आग की सूचना देने के लिए इस बार 35 रिपीटर, 506 वायरलेस सेट, 1631 हैंडसेट और 199 मोबाइल सेट की व्यवस्था की गई है। मध्य हिमालयी क्षेत्र के वनों में हर साल होने वाली आग की घटनाओं पर नजर रखने वाले उत्तराखंड वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष डॉ. एसपी सती वन विभाग के इन दावों पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि वन विभाग हर वर्ष ऐसे दावे करता है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों हेक्टेयर वन जल जाते हैं। वे कहते हैं कि उत्तराखंड के ज्यादातर घने जंगल बेहद दुर्गम हैं, इन जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए आज तक विभाग कोई कारगर उपाय नहीं कर पाया है। ●

प्लास्टिक का हैंगिंग गमला

ऊपर तस्वरा में दिख रहे शख्स नागेन्द्र जी हैं जो रांची कचहरी के पास फूल के पेड़ पौधों के नर्सरी की दूकान चलाते हैं। इनकी दूकान में रंग बिरंगे प्लास्टिक के गमले हैं जिन्हें टांगा भी जा सकता है। अब अगर आप के पास बागवानी लायक जगह नहीं तो आप ऐसे गमले लेकर उनमें पौधे लगा कर अपनी बालकनी में टांग जरूर सकते है। आप के बागवानी का शौक भी पूरा हो जायेगा।

पेड़ में कील ठोकना गैरकानूनी है, खुद रांची नगर निगम हीं ऐसा कर रहा है

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।